1	2	3	4	6
36	Palamau	3	..	2
37	Patna	5	1	2
38	Purnea	..	..	1
39	Ranchi	18	15	4
40	Rohtas	8	1	1
41	Saharsa	11	2	2
42	Sahibganj	..	5	2
43	Samastipur	8	1	3
44	Saran	9	3	3
45	Sitamarhi	4	2	2
46	Siwan	7	..	2
47	Supaul	7	1	1
48	Vaishali	7	1	2
49	West Champaran	7	..	1
50	West Singhbhum	1	6	4
	TOTAL	268	70	90

आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधाएं

35. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । तथापि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूर-संचार सुविधाओं के विकास के लिए आदिवासी उप-योजना तैयार की गई है । मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों का पता लगाया है । मध्य प्रदेश के पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में जिन औद्योगिक विकास केन्द्रों का पता लगाया है ; उनके लिए 1994–95 की दूरसंचार विकास योजना का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

औद्योगिक विकास केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	जिला	विकास केन्द्रों के नाम	1994–95 की योजना
1.	भालनपुर		512 (पोर्ट)
2.	देवास		5 के-सीडॉट
3.	धार	पीथमपुर (आदिवासी)	512 पोर्ट
4.	झबुआ	मेघनगर (आदिवासी)	/512 पोर्ट
5.	मुरैना	बनमोर	+ 512 पोर्ट
6.	रीवा	रीवा	+ 512 पोर्ट
7.	रायपुर	उरला	+ 1000 विस्तार
8.	शाजापुर	भाकशी	+ 512 पोर्ट
9.	सीधी	वैधान (आदिवासी)	+ 512 पोर्ट

Privatisation of telecom industry

86. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANAN SAHU:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a policy decision regarding privatisation of telecom industry;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the highest limit, if any fixed on the percentage of foreign eqsity participation in telecom industry; and

(d) the steps so far taken in pursuance thereof, by way of clearing the investment proposals pending with Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes Sir.

(b) The New Industrial Policy announced by the Government in July, 91 has permitted the setting up of Telecom manufacturing Industries in the private sector. Under this policy, no industrial licence is required for the manufacturer of any type of telecom equipment.

(c) Under this policy, proposals for manufacture of telecom equipment with foreign equity participations upto 51 percent are permitted under automatic approval and those involving more than 51 percent are considered on case to case basis.

(d) All applications for foreign collaborations with foreign equity upto 51 per cent falling under the automatic approval procedure are approved by RBI, Bombay. All other applications including the applications involving foreign enquity above 51 per cent are considerel by the FIPB and approved on case to case basis.